ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 244-246**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ एवं समाधान : एक विश्लेषण

प्रिन्स यादव
शोध अध्येता– रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-20.03.2025, Revised-25.03.2025 Accepted-30.03.2025 **E-mail : py43018@gamil.com**

सारांशः हिन्द एवं प्रशांत महासागर एक–दूसरे से रणनीतिक रूप से निकटता से जुड़े हैं,भौगोलिक तौर पर हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिन्द–प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिन्द प्रशांत एक ऐसा केंद्रीय भौगोलिक क्षेत्र है जो कई तरह से वैश्विक एजेंडा तय करता रहा,इस विविधता भरे ऊर्जावान मगर जटिल क्षेत्र में भू–राजनीतिक तनाव, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, आर्थिक आयाम और पर्यावरण की चिंताएं आपस में मिलती रही हैं। हिन्द प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती चीन की उपस्थिति है। चीन अपने 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के माध्यम से विश्व की महाशक्ति के रूप में अपने को बदलने के लिये दुनिया के विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी पर भारी निवेश कर रहा है। उसकी इस पहल का उद्देश्य हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना भी है।चीन अपनी काल्पनिक नीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के ज़रिये भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को इस क्षेत्र के देशों द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। यूरोपीय संघ, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की हिन्द–प्रशांत रणनीतियाँ सभी शांतिपूर्ण हिन्द–प्रशांत के विकास को सुनिश्चित करने में भारत के साथ जुड़ने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। भारत के साथ जुड़ने और स्वतंत्र, खुले समावेशी" इंडो–पैसिफिक के बाद के दृष्टिकोण का समर्थन करने के इच्छुक हैं। साथ में उन्हें एक इंडो–पैसिफिक आर्किटेक्चर का निर्माण करना होगा जो उभरती चुनौतियों का जवाब देने और क्षेत्र के देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने में सक्षम हो।

कुंजीभूत शब्द– हिंद–प्रशांत,समाधान, वैश्विक एजेंडा, व्यावहारिक सहयोग, उपकरणों, दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियाँ, आर्थिक

प्रस्तावना– इंडो–पैसिफिक शब्द पहली बार भू–राजनीति में अकादमिक उपयोग में किया गया था। "इंडो–पैसिफिक"अवधारणा वेइमर जर्मनी में प्रसारित हुई,और जापान के बीच फैल गई। जर्मन राजनीतिक समुद्र विज्ञानियों ने एक "इंडो–पैसिफिक" की कल्पना की, जिसमें "यूरो–अमेरिका" के खिलाफ जर्मन सहयोगियों के रूप में उपनिवेश विरोधी भारत और चीन शामिल थे। 2010 के दशक के उत्तरार्ध से, "इंडो–पैसिफिक" शब्द का उपयोग भू–राजनीतिक चर्चा में तेजी से किया जा रहा था। इसका ऑस्ट्रेलिया,जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक समूह चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या "क्वाड" के साथ एक "सहजीवी संबंध" भी है ।यह तर्क दिया गया है कि यह अवधारणा लोकप्रिय "मानसिक मानचित्रों" में बदलाव ला सकती है कि दुनिया को रणनीतिक दृष्टि से कैसे समझा जाता है।क्षेत्र के लिए पुरानी शर्तों को ओवरलैप करने पर टिप्पणी करते हुए, राजनीतिक वैज्ञानिक अमिताव आचार्य ने कहा कि एक अवधारणा के रूप में, "'एशिया' राष्ट्रवादियों द्वारा,'एशिया–प्रशांत' अर्थशास्त्रियों द्वारा,'पूर्वी एशिया' संस्कृतिवादियों द्वारा बनाया गया था, जबकि 'इंडो' –पैसिफ़िक' रणनीतिकारों द्वारा'" ।अपने व्यापक अर्थ में, भूराजनीतिक रूप से शब्द हिन्द महासागर या प्रशांत महासागर के आसपास के सभी देशों और द्वीपों को कवर करता है, जिसमें मुख्य भूमि अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्र शामिल हैं जो इन महासागरों की सीमा पर हैं, जैसे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका, हिन्द महासागर क्षेत्र जैसे कि केर्गुएलन द्वीप और सेशेल्स,मलय द्वीपसमूह (जो हिन्द महासागर और प्रशांत दोनों की सीमा के भीतर है), जापान , रूस और प्रशांत की सीमा से लगे अन्य सुदूर पूर्व राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया और उनके पूर्व में सभी प्रशांत द्वीप समूह साथ ही प्रशांत महासागर के राष्ट्र अमेरिका जैसे कनाडा या मैक्सिको। आसियान देशों (दक्षिण पूर्व एशिया और मलय द्वीपसमूह के रूप में परिभाषित) को भौगोलिक रूप से राजनीतिक इंडो–पैसिफिक के केंद्र में माना जाता है। हिन्द–प्रशांत एक हालिया अवधारणा है,लगभग एक दशक पहले दुनिया ने हिन्द–प्रशांत के बारे में बात करना शुरू किया; इसका उदय काफी महत्त्वपूर्ण रहा है।इस शब्द की लोकप्रियता के पीछे के कारणों में से एक यह है कि हिन्द एवं प्रशांत महासागर एक–दूसरे से रणनीतिक रूप से निकटता से जुड़े हैं।साथ ही एशिया आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसका कारण यह है कि हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर समुद्री मार्ग प्रदान करते हैं। दुनिया का अधिकांश व्यापार इन्हीं महासागरों के माध्यम से होता है।भौगोलिक तौर पर हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिन्द–प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिन्द–प्रशांत एक ऐसा केंद्रीय भौगोलिक क्षेत्र बना रहा, जो कई तरह से वैश्विक एजेंडा तय करता रहा. इस विविधता भरे और ऊर्जावान मगर जटिल क्षेत्र में भू–राजनीतिक तनाव, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, आर्थिक आयाम और पर्यावरण की चिंताएं आपस में मिलती रहीं।इसकी बहुआयामी चिंताओं से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए बहुत सावधानी और सहयोग वाले तरीक़े अपनाने की ज़रूरत है. हिन्द–प्रशांत के भू–राजनीतिक बदलावों के क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक राजनीति पर दूरगामी नतीजे निकल सकते हैं और इनका असर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और विकास संबंधी ढांचे पर भी पड़ने वाला है।सुरक्षा इन चुनौतियों में गहरी होती सैन्य चिंताएं, गंभीर होते इलाक़ाई विवाद, ग़ैर पारंपरिक ख़तरे और बड़ी ताक़तों के आपसी संघर्ष के व्यापक आयाम भी शामिल हैं.।

हिन्द–प्रशांत और भविष्य की चुनौतियाँ– हिन्द–प्रशांत बहु–ध्रुवीयता और पुनर्संतुलन में चल रहे मंथन के केंद्र में है जो समकालीन परिवर्तनों की विशेषता है, जिसमें देशों के विचलन और पूरकता शामिल है और स्थिरता पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण को जोड़ती है।जबकि क्षेत्र को महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता द्वारा आकार दिया जा रहा है, महामारी ने सुरक्षा की धारणा पर संवाद को बदल दिया है। वैक्सीन कूटनीति, समान वितरण और चिकित्सा उपकरणों, परीक्षण किट आदि तक पहुंच ने राष्ट्रों को स्वास्थ्य सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में शामिल करने के लिए प्रेरित किया है।

इस क्षेत्र ने महामारी के जवाब में क्वाड नीति की सोच में एक विकास देखा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 ने '21 वीं सदी की चुनौतियों के लिए व्यावहारिक सहयोग' को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पहल की घोषणा की (जोर जोड़ा गया);

1. सुरक्षित और प्रभावी टीकों के उत्पादन और पहुंच में वृद्धि करने सहित कोविड–19 महामारी को समाप्त करना,

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

2. उच्च–मानक अवसंरचना को बढ़ावा देना,
3. जलवायु संकट का मुकाबला करना
4. उभरती प्रौद्योगिकियों, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा पर भागीदारी
5. हमारे सभी देशों में अगली पीढ़ी की प्रतिभा को विकसित करना।

क्वाड द्वारा पहचानी गई चुनौतियाँ दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियाँ हैं जिनके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी। वे उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पारंपरिक सुरक्षा जरूरतों से भी आगे जाते हैं जो भविष्य में राष्ट्रों को प्रभावित करेंगे। क्वाड के हिस्से के रूप में, भारत ने सुरक्षा सोच में विकास का स्वागत किया है और 'दुनिया की फार्मेसी' महामारी को समाप्त करने के लिए आवश्यक टीके उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।महामारी अपने वर्तमान स्वरूप में वैश्वीकरण के भविष्य पर कई सवालों के साथ अभूतपूर्व आर्थिक चुनौतियां भी लेकर आई है। इसने देशों को लचीली अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए मजबूर किया है जो प्रतिस्पर्धी होने के साथ–साथ महामारी की स्थितियों का सामना करने में सक्षम होंगे। अमेरिका ने अपने इंडो–पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है जो व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं और टिकाऊ बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण में मदद करेगा; सभी क्षेत्र जो भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में मदद करेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आम मुद्दा यात्रा प्रतिबंधों, सीमाओं को बंद करने और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले दबावों का सामना करना पड़ रहा था। मामलों में असमान वृद्धि और गिरावट के साथ, देशों ने प्रतिबंधों, लॉकडाउन आदि को जारी रखने के बारे में व्यक्तिगत नीतिगत निर्णय लिए हैं। उदाहरण के लिए, चीन की शून्य–कोविड सहिष्णुता नीति के कारण लॉकडाउन जारी है। ऐसी स्थिति में विविधता लाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए, भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल पर काम कर रहा है। यह पहल भविष्य के लिए टिकाऊ, सुरक्षित और लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने का एक प्रयास है। एक और मुद्दा जिसने महामारी के दौरान महत्व प्राप्त किया, वह था मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने की आवश्यकता। 'वर्क फ्रॉम होम'/'स्टडी फ्रॉम होम' व्यवस्थाओं ने व्यवसाय करने और शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल स्पेस का उपयोग बढ़ा दिया है।

टेलीमेडिसिन परामर्श में वृद्धि के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होंगी, डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने की इसी आवश्यकता के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकता बढ़ेगी। कनेक्टिविटी का एक और महत्वपूर्ण कारक भौतिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है। पूरे क्षेत्र में माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही समय की मांग बनी हुई है। हिंद–प्रशांत के प्रति भारत के दृष्टिकोण में अपने पड़ोसियों के बीच अंतर–संपर्क में अंतर को पाटने की आवश्यकता शामिल है। भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही की अनुमति देगा, जिससे देशों को अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जैसे–जैसे महामारी कम होने लगी है, क्षेत्रीय भू–राजनीति और नई चुनौतियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो आने वाले वर्षों में हिंद–प्रशांत को प्रभावित करेंगे। चीन के मुखर व्यवहार ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका को शांति, लोकतंत्र, समृद्धि और नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए साझा समर्थन के आधार पर अधिक सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक नया सुरक्षा गठबंधन, ।न्झै बनाने के लिए प्रेरित किया है। ।न्झै गठबंधन का उद्देश्य 'एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करने' के लिए काम करना है। इस क्षेत्र को रूस से बढ़ते हितों का जवाब देने की भी आवश्यकता होगी। इंडो–पैसिफिक अवधारणा को खारिज करते हुए, एशिया की ओर बढ़ने के रूस के प्रयास अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे क्योंकि 'पश्चिम' के साथ इसके संबंध बिगड़ रहे हैं और यह अपने सुदूर पूर्व क्षेत्र को विकसित करने पर जोर देता है। यह देखा जाना बाकी है कि क्षेत्र के देश रूस के प्रस्तावों का जवाब कैसे देते हैं, जबकि वे चीन, उनके मुख्य आर्थिक भागीदार और अमेरिका, उनके प्रमुख सुरक्षा भागीदार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का भारत–प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। संघर्ष का तत्काल प्रभाव देशों की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं में दिखाई दे रहा है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है। संघर्ष के परिणामस्वरूप कुछ खाद्यान्नों और उत्पादों की कमी क्षेत्र के देशों में गरीब और सीमांत समुदायों को प्रभावित करेगी। संघर्ष से मुद्रास्फीति में परिणामी वृद्धि और महामारी की अंतर्निहित चुनौतियों के कारण आर्थिक सुधार धीमा हो गया है। विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए संघर्ष का एक और दुष्प्रभाव अफगानिस्तान से ध्यान हटाने का रहा है। जैसा कि युद्धग्रस्त देश अस्थिर बना हुआ है, मानवीय सहायता पर निर्भर है और सत्ता के लिए क्षेत्रीय अंशों के साथ, भविष्य में इस क्षेत्र के लिए व्यापक सुरक्षा निहितार्थ होंगे। यूक्रेन में मौजूदा संघर्ष और अफगानिस्तान पर चीन और रूस द्वारा उठाए गए पिछले रुख से संकेत मिलता है कि ध्रुवीकरण यहां रहेगा। यह और तेज हो सकता है क्योंकि यूक्रेन में संघर्ष जारी है और यह क्षेत्र के देशों को प्रभावित करेगा।

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियाँ– इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती चीन की उपस्थिति है। चीन अपने 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के माध्यम से विश्व की महाशक्ति के रूप में अपने को बदलने के लिये दुनिया के विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी पर भारी निवेश कर रहा है। उसकी इस पहल का उद्देश्य हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना भी है।चीन अपनी काल्पनिक नीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के ज़रिये भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है तथा हिंद–प्रशांत क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज़ करा रहा है।हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को इस क्षेत्र के देशों द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। यूरोपीय संघ, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की हिंद–प्रशांत रणनीतियां सभी शांतिपूर्ण हिंद–प्रशांत के विकास को सुनिश्चित करने में भारत के साथ जुड़ने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। तदनुसार, भारत की नीतिगत सोच में हिंद–प्रशांत क्षेत्र के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, इसकी विदेश नीति के विकल्पों ने इसके सुरक्षा वातावरण को प्रभावित किया है।हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) दृष्टिकोण और हिंद–प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) द्वारा निर्देशित है। सागर एक सुरक्षित, महफूज़ और स्थिर हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भागीदारों के साथ काम करने का भारत का दृष्टिकोण है। भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहता है और सूचना/खुफिया जानकारी साझा करने, तटीय निगरानी, बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग करके अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। आईपीओआई का मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, निर्भयता और स्थिरता सुनिश्चित करना है और ऐसा करने के लिए सात स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। वे भारत को समुद्री सुरक्षा, समुद्री संसाधन प्रबंधन, और नीली अर्थव्यवस्था के विकास, समुद्री संपर्क, आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण सहित

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय रूप से या बहुपक्षीय और बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर अपने इंडो–पैसिफिक भागीदारों के साथ जुड़ने की अनुमति देते हैं। दोनों पहल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संपर्क का अर्थ है कि कहीं भी अस्थिरता भारत की समुद्री सुरक्षा पर भी प्रभाव डालेगी। यह विचार विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर द्वारा व्यक्त किया गया था जब उन्होंने कहा था कि, "यह एक समुद्री शताब्दी बनी हुई है, और हिंद–प्रशांत क्षेत्र के ज्वार निश्चित रूप से इसके भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे। और भारत अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर महासागरों को शांतिपूर्ण, खुला और सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास करेगा, और साथ ही, अपने संसाधनों के संरक्षण और इसे स्वच्छ रखने में योगदान देगा।"भारत–प्रशांत पर वैश्विक शक्तियों का अभिसरण भी बढ़ रहा है, जो इस क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पहलों के प्रसार से स्पष्ट है, जिसमें भारत तेजी से भागीदार बन रहा है। इंडो–पैसिफिक विकसित हो रहे वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रमुख केंद्र बन गया है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक प्रवाह और महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता के पुनरुद्धार के साथ, हिंद–प्रशांत के देश प्रतिक्रिया कर रहे हैं और नई चुनौतियों का जवाब दे रहे हैं जो मौजूदा खतरों से निपटने के लिए जारी हैं। यह लेख कुछ कारकों की पहचान करता है जो आकार दे रहे हैं और भविष्य के इंडो–पैसिफिक की रूपरेखा में योगदान देंगे।

समाधान– हिंद–प्रशांत क्षेत्र के देशों की अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्र और हवाई क्षेत्र में सामान्य स्थानों के उपयोग के अधिकार के रूप में समान पहुँच होनी चाहिये, जिसके लिये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नेविगेशन की स्वतंत्रता, अबाधित वाणिज्य तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता होगी। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, परामर्श, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहार्यता तथा स्थिरता के आधार पर क्षेत्र में कनेक्टिविटी स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिये समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) आवश्यक है। MDA का तात्पर्य समुद्री पर्यावरण से जुड़ी किसी भी गतिविधि की प्रभावी समझ से है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है।

बहुध्रुवीयता: सुरक्षा, शांति और कानून का पालन करने की प्रकृति इस क्षेत्र के आसपास के देशों के लिये महत्त्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में बहुध्रुवीयता भी आएगी। इस क्षेत्र के छोटे राज्य भारत से अपेक्षा करते हैं कि वह किसी अवसर या संकट के जवाब में कार्रवाई करे और आर्थिक एवं सैन्य दोनों तरह से अपने विकल्पों को व्यापक बनाने में उनकी मदद करे। भारत को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये।

निष्कर्ष– हिंद–प्रशांत क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक रूप से वैश्विक महत्त्व के केंद्र के रूप में उभर रहा है। यदि इस क्षेत्र के हितधारक एक खुले, नियम–आधारित व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये कार्य नहीं करते हैं, तो सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती रहेगी, जिसका प्रभाव दुनिया भर पर पड़ना संभावित है। वर्तमान में जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा सहयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। संपूर्ण हिंद–प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये इस सहयोग को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र पिछले एक दशक में अंतरराष्ट्रीय भू–राजनीतिक और भू–आर्थिक वातावरण में बदलाव के कारण बढ़े हुए फोकस का क्षेत्र रहा है। यह प्रतिस्पर्धा और सहयोग के क्षेत्र के रूप में उभरा है। महामारी के कारण कई चुनौतियों और अवसरों को बढ़ाया गया है,हिंद–प्रशांत के समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी बनाना भारत–प्रशांत के लिए भारत की नीति का मूल बना रहेगा। जैसे–जैसे इंडो–पैसिफिक का प्रभुत्व बढ़ता है, प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ी इस क्षेत्र के लिए अपनी रणनीतियों को स्पष्ट करते हैं, यह स्पष्ट हो गया है कि वे भारत के साथ जुड़ने और "स्वतंत्र, खुले और समावेशी" इंडो–पैसिफिक के बाद के दृष्टिकोण का समर्थन करने के इच्छुक हैं। साथ में उन्हें एक इंडो–पैसिफिक आर्किटेक्चर का निर्माण करना होगा जो उभरती चुनौतियों का जवाब देने और क्षेत्र के देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने में सक्षम हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रामसूरत पांडे"राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध" प्रकाश बुक डिपो बरेली, संस्करण 2016 पृष्ठ संख्या 178
2. बी. एल. फाडिया "अंतर्राष्ट्रीय संबंध" साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा; संस्करण 2017 पृष्ठ संख्या 517
3. जे.एम.श्रीवास्तव" राष्ट्रीय सुरक्षा "प्रत्यूष पब्लिकेशन दिल्ली संस्करण 2014 पृष्ठ संख्या 530
4. अशोक कुमारऔर विपुल अनेकांत "भारत की आतंरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां, एमसी ग्रावा हील एजुकेशन चेन्नई इंडिया,2020 पृष्ठ संख्या 10:13
5. एम. गणपति, भारत की विदेश नीति में हिंद–प्रशांत क्षेत्र का महत्व विदेश मंत्रालय,भारत सरकार, सिक्किम विश्वविद्याल, विशिष्ट व्याख्यान 18 सितम्बर,2019
6. शिशिर उपाध्याय, "चीन का समुद्री आयाम' बीआरआईः भारत के लिए निहितार्थ", 'द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिवः इंप्लीटेंस फॉर इंडिया' में, (सं.) मनीष, पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली, 2021.
7. जीवीसी नायडू, "भारत और समुद्री रेशम मार्ग", 'बेल्ट एंड रोड पहलः भारत के लिए निहितार्थ', (सं.) मनीष, पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली, 2021
8. क्रेग सिंगलटन, "बीजिंग की नजर हिंद–प्रशांत क्षेत्र में नए सैन्य अड्डों पर है," विदेश नीति ,7 जुलाई, 2021,
9. निक पेरी और जिम गोमेज़, "चीन के नेता शी ने एशिया–प्रशांत में 'शीत युद्ध' के खिलाफ चेतावनी दी है," एबीसी न्यूज,11 नवंबर, 2021,
10. "महासागर राष्ट्रः एक इंडो–पैसिफिक द्वीप संवाद," अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट, सितंबर 2021,
11. जोशुआ टी व्हाइट, "चीन की हिंद महासागर महत्वाकांक्षाएं," ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशंस, जून 2020,
12. किंग्सले इघोबोर, "कोविड–19, मॉरीशस में तेल रिसाव छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों की कमजोरियों पर प्रकाश डालता है। अफ़्रीका नवीनीकरण," संयुक्त राष्ट्र, 24 फरवरी, 2021,
13. हेलेन रेगन और सोफी जियोंग, "श्रीलंका का जलता हुआ मालवाहक जहाज 'सबसे खराब पर्यावरणीय आपदा' बनने की राह पर है," सीएनएन, 1 जून, 2021,
14. रंगा सिरीलाल और शिहर अनीज़, "मोदी के श्रीलंका दौरे पर भारत चीन पर बढ़त चाहता है," रॉयटर्स, 13 मार्च 2015,
15. "सचिव एंटनी जे. ब्लिंकन और कार्यवाहक फ़िजी प्रधान मंत्री अयाज़ सईद–खैयुम एक संयुक्त प्रेस उपलब्धता में," अमेरिकी विदेश विभाग, 12 फरवरी, 2022,
16. शैनन टिएज़ी, "ताइवान से स्विच करने के बाद किरिबाती राष्ट्रपति ने चीन हिन्द प्रशांत क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियां एवं समाधानःएक विश्लेषण